बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 74

उच्च वृद्धि पर दें ध्यान

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अर्थशास्त्रियों ने सन 2030 तक की वैश्विक वृद्धि को लेकर एक अनुमान प्रस्तुत किया है। उसके मुताबिक एशिया की सात अर्थव्यवस्थाएं इस अवधि में 7 फीसदी की दर से बढ़ेंगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत इनमें से एक होगा लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कुछ अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में धीमी गति से विकसित होगा। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि सन 2030 तक बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक होगी। इस बीच वियतनाम, जिसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से केवल 30 फीसदी अधिक है, उसकी प्रति व्यक्ति आय सालाना 10,000 डॉलर से अधिक हो जाएगी। इस प्रकार वह प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत से दोगुनी समृद्धि वाला देश हो जाएगा।

भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इन देशों से तुलना बहुत आश्वस्त नहीं करती। ऐसे समय में जबकि छोटे देश कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, चीन को पीछे छोड़ने या अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़ने की बात बहुत आश्वस्त नहीं करती। इस अवधि में भारत प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ सके, इसके लिए क्या करना होगा?

अब से लेकर 2030 तक वृद्धि के लिए स्थायी राह पर विचार करते हुए स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अर्थशास्त्री अनुमान जताते हैं कि जो अर्थव्यवस्थाएं जिंस या विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात कर सकती हैं उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। यह बात ध्यान देने वाली है कि बीते वर्षों के दौरान निर्यात के मोर्चे पर बांग्लादेश और वियतनाम दोनों का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा है। इसकी एक वजह भारतीय विनिर्माण का प्रतिस्पर्धी न होना भी है। प्रतिस्पर्धा की यह कमी वस्त्र क्षेत्र के अलावा भी है। हाल के वर्षों में संरक्षणवादी रुख अपनाया गया है लेकिन वह भी मददगार नहीं साबित हुआ क्योंकि इसके कारण देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनाने में दिक्कत आती है। ई-कॉमर्स क्षेत्र में भारी भरकम निवेश करने वाले निवेशकों समेत अन्य निवेशकों के साथ मनमाना व्यवहार भी इस क्षेत्र में हमारे पिछड़ने की एक वजह है। अगली सरकार को यह छवि बदलनी होगी और ऐसी धारणा विकसित करने की दिशा में काम करना होगा कि विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के लिए देश में स्थिर माहौल है। साथ ही यह भी कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के घटकों के केंद्र के रूप में भारत सुरक्षित है।

व्यापक प्रश्न यह है कि निजी निवेश में इजाफे के बिना वृद्धि दर में बढ़ोतरी कैसे लाई जा सकती है। फिलहाल निवेश अतीत के वर्षों की ऊंचाई से काफी कम है। बीते चार-पांच वर्ष से इसमें ठहराव भी देखने को मिल रहा है। बीती कुछ तिमाहियों में अवश्य थोड़ा सुधार देखने को मिला है। निवेशकों का यकीन नए सिरे से बहाल करना बहुत अहम है। निजी कारोबारी बचत में इजाफा भी आवश्यक है क्योंकि तभी ऐसा निवेश संभव हो पाएगा। अभी भी काफी पूंजी तंत्र में फंसी हुई है। तेजी और प्रोत्साहन वाले वर्षों का ऋण अभी तक पूरी तरह निपट नहीं सका है। कई बैलेंसशीट अभी भी कर्ज के बोझ में दबी हैं। परंतु जरूरत यह है कि निर्यात के जरिये निवेश और आय के नए अवसर और संभावनाएं तलाश किए जाएं। नया पूंजीगत व्यय अक्सर रोजगार तैयार करने और आम घरों की वित्तीय बचत बढ़ाने में मदद करता है। अगर भारत को उभरती अर्थव्यवस्थाओं में श्रेष्ठ बनना है तो इन बातों को प्राथमिकता देनी होगी। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि कामगार वृद्धि और अवसरों का लाभ लेने के लिए तैयार हों। दूसरे शब्दों में शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता में रखना अनिवार्य है।

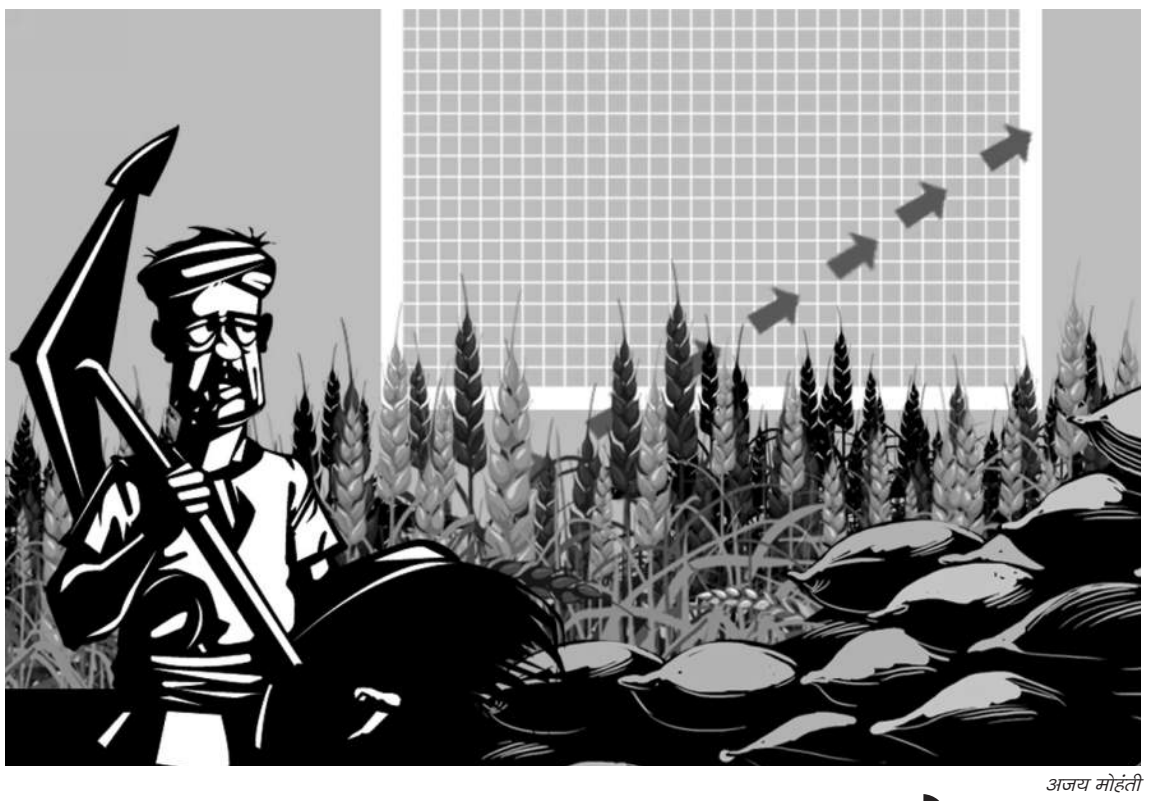

अजय मोहंती

भारत बन सकता है कृषि क्षेत्र की ताकत

हममें से कई लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि कृषि क्षेत्र का निर्यात वाहन क्षेत्र या कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र के निर्यात से अधिक है। विस्तार से बता रहे हैं **अजय शाह**

खाद्यान्न के अभाव की मानसिकता काफी हद तक आधुनिक भारत से मेल नहीं खाती। उपज बढ़ने के साथ स्थानीय कीमतों में गिरावट रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि इस क्षेत्र को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाए। हमारा देश हर वर्ष कृषि क्षेत्र में करीब 4,000 करोड़ डॉलर का निर्यात करता है। यह निर्यात कपड़ा एवं वस्त्र क्षेत्र के कुल निर्यात से भी अधिक है। कृषि क्षेत्र को लेकर हमको अपना वैश्विक नजरिया और अधिक अंतरराष्ट्रीय बनाना होगा।

भारत में खुद ही देश को लेकर ऐसा नजरिया बन चुका है कि यह अत्यधिक आबादी और खाद्यान्न की कमी वाला देश है। कई दशक पहले ऐसा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। देश में खेती की जमीन की कमी नहीं है। मौसम भी एक वर्ष में कई फसल लेने में सहायक है। शुरुआत में हमारी उपज बहुत कम थी लेकिन अब उसका स्तर बहुत सुधर चुका है।

उपज में सुधार के साथ ही आबादी का बढ़ना निरंतर धीमा हो रहा है। हमारे लिए यह संभव नहीं है कि जितना अन्न उपज रहा है उसकी खपत कर सकें। शायद घरेलू बाजार में खाद्यान्न कीमतों में गिरावट की यह भी एक वजह है। इन बातों ने कृषि उत्पादों के निर्यात की बुनियाद तैयार की। वर्ष 2013 तक भारत कृषि निर्यात के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ चुका था। उसने इस क्षेत्र में बीते दशक के मुकाबले सबसे ऊंची वृद्धि दर हासिल की। कृषि क्षेत्र का व्यापार/जीडीपी अनुपात 2008-09 के 11.8 फीसदी से बढ़कर 2018-19 तक 15.2 फीसदी हो गया। देश के श्रम आधारित निर्यात की चर्चा अक्सर वाहन और वस्त्र उद्योग तक सीमित रहती है। हममें से कई लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि कृषि क्षेत्र का निर्यात अब वाहन, कपड़ा और वस्त्र उद्योग से अधिक है। इसके बावजूद हाल के वर्षों में इसकी वृद्धि में ठहराव देखा गया है। वर्ष 2001-2004 और 2011-2014 के बीच हमने कृषि क्षेत्र के निर्यात में हर साल 3,400 करोड़ डॉलर जोड़े। उसके बाद के वर्षों में वृद्धि देखने को नहीं मिली। यह देश के मौजूदा कृषि संकट का एक तत्त्व हो सकता है। निरंतर निर्यात बाजार से जुड़ाव हमें एक खास न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित करता है।

अन्य देशों के संरक्षणवाद या सब्सिडी से परे एकतरफा वैश्विक एकीकरण हमारे लिए अवसर लाया है। ऐसे अंतरराष्ट्रीयकरण को लेकर कुल चार थीम हैं। इन्हें अन्य उद्योगों के क्षेत्र में समझा जा चुका है और अब कृषि की बारी है।

पहली थीम है विशेषज्ञता की। भारत सॉफ्टवेयर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करता रहा है लेकिन हार्डवेयर अथवा डेटा सेंटर चलाने के क्षेत्र में उसका प्रदर्शन उल्लेखनीय नहीं रहा है। ऐसे में भारत के लिए बेहतर यही होगा कि वह सॉफ्टवेयर बनाए और निर्यात करे जबकि डेटा सेंटर दुनिया में अन्य स्थानों पर किराये से ले।

इसी प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकरण से देश के कृषि क्षेत्र में भी बदलाव आएगा। व्यापारिक शर्तों के अधीन हम उन चीजों के उत्पादन से दूरी बनाएंगे जो अन्य जगह बेहतर उत्पादित हो रही हैं। मिसाल के तौर पर गन्ना और गेहूं आदि। इसके स्थान पर हम उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जिनमें हमारी विशेषज्ञता है। उदाहरण के लिए फल और सब्जियां।

दूसरी थीम है राजनीतिक अर्थव्यवस्था। घरेलू नीति प्रक्रिया निष्क्रिय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में तब्दील हो रही है जहां विशेष हित वाले समूहों का दबदबा है।

अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव एक नया परिदृश्य रचने में सहायता करता है। हमारे देश में गठबंधन करना आसान है। कई विशिष्ट हित समूह मिलकर सफलतापूर्वक निर्यात कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र बहुत लंबे समय से नीतिगत प्रगति के क्षेत्र में ठहरा हुआ है। अब जबकि व्यापार और जीडीपी अनुपात 15 फीसदी है और निर्यात 4,000 करोड़ डॉलर हो चुका है तो कृषि नीति को लेकर नई संभावनाएं उत्पन्न हो चुकी हैं।

अंतरराष्ट्रीयकरण कई घरेलू पहेलियां हल करता है। उदाहरण के लिए देश में जिंस वायदा बाजार का क्रियान्वयन आसान नहीं है लेकिन एक बार अंतरराष्ट्रीयकरण होने के बाद देश के बाहर इन बाजारों में कारोबार किया जा सकेगा। भारत के लोग देश के बाहर वायदा बाजार की कीमत के आधार पर भंडारण या बुआई के निर्णय लेंगे। अंतरराष्ट्रीयकरण घरेलू नीति की समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है।

तीसरी थीम है दक्षिण एशिया में व्यापार। भौतिक नजदीकी अंतरराष्ट्रीय कारोबार के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे लिए सबसे अहम व्यापारिक अवसर आसपास के क्षेत्र में ही हैं। कृषि पर यह बात और अधिक लागू होती है क्योंकि इसमें परिवहन लागत की अहम भूमिका है। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा ताकि दक्षिण एशिया में सुगमता से व्यापार का लाभ हासिल किया जा सके।

चौथी थीम है निरंतर संबद्धता। कई लोगों ने इस बात पर टिप्पणी की है कि कैसे भारत को अविश्वसनीय विक्रेता माना जाता है क्योंकि समय-समय पर इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगते रहे हैं। समस्या कहीं अधिक गहरी है। निर्यात सामान्य मसला नहीं है। इसके लिए जटिल संगठनात्मक पूंजी और कारोबारी रिश्तों की आवश्यकता होती है। अगर वस्त्र या वाहन क्षेत्र के निर्यात पर आए दिन प्रतिबंध लगे तो जाहिर है इसका असर निवेशकों पर पड़ेगा। इसमें सांस्थानिक, प्रक्रिया डिजाइन, कारेबारी रिश्ते आदि सभी क्षेत्रों के निवेश पर पड़ने वाला असर शामिल है। भारतीय कंपनियों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल होना जटिल नियोजन की मांग करता है। इसके लिए कई वर्ष की तैयारी चाहिए।

यही बात उन विदेशी कंपनियों पर भी लागू होती है जो भारत के साथ कारोबार करना चाहती हैं। ऐसे प्रतिबंध भारत में निवेश की कंपनियों की इच्छा पर रोक लागते हैं। इससे भारत की निर्यात क्षमता प्रभावित होती है। हमारा आधा वैश्विक कारोबार बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ होता है। निर्यात के लिए हमें ऐसी वैश्विक कंपनियों की आवश्यकता है जो हमारे यहां निवेश की प्रतिबद्धता जताएं।

प्रतिबंध लगने और उठने का दौर खाद्य असुरक्षा की उपज रहा है। अब हालात बदल चुके हैं। देश की आबादी कुल उत्पादित खाद्यान्न की खपत नहीं कर सकती। भविष्य में उपज में लाभ समस्या को हल करने वाले साबित होंगे। हम कृषि नीति को उपभोक्ताओं और किसानों के बीच एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं। अगर हम एक बार अपना नजरिया बदलकर वैश्विक कारोबार में शामिल हो गए तो हालात में बदलाव आ जाएगा। अगर हम कृषि जिंसों का आयात बढ़ाने में कामयाब रहे तो इसका लाभ हर भारतीय को मिलेगा। भूमि का इस्तेमाल भी कम मूल्य वाली वस्तुओं से उच्च मूल्य वाली उपज की ओर होगा।

उम्मीदवार का मानसिक संतुलन जांचता है तनावपूर्ण साक्षात्कार

इंसानी पहलू

श्यामल मजूमदार

नैशनल एविएटर्स गिल्ड ने अब बंद हो चुकी एयरलाइन जेट एयरवेज के पायलटों का साक्षात्कार करते समय स्पाइसजेट के कुछ कर्मचारियों की टिप्पणियों पर सख्त एतराज जताया है। साक्षात्कार के दौरान स्पाइसजेट के एक अधिकारी ने कथित तौर पर कहा था कि वह जेट एयरवेज के पायलटों को नौकरी देकर अहसान कर रहे हैं। पायलट यूनियन ने इसके विरोध में अपना बयान जारी किया है। हालांकि इन आरोपों से स्पाइसजेट के इनकार के बाद उसे संदेह का लाभ मिलना चाहिए लेकिन ऐसे विषाक्त साक्षात्कार असामान्य बात नहीं हैं।

काऊबॉय शैली में किए जाने वाले ऐसे साक्षात्कारों में कमर के नीचे निशाना साधने वाले सवाल पूछे जाते हैं। अमूमन ऐसी शैली वही कंपनियां अपनाती हैं जिनकी अपनी कार्य-संस्कृति अच्छी नहीं होती है या कुछ घमंडी कॉर्पोरेट दिग्गजों को यह गुमान होता है कि उनके लिए काम करने के वास्ते हर कोई कुछ भी करने को तैयार है। ऐसे लोगों को यह अहसास ही नहीं होता है कि वे उम्मीदवारों को अपने संस्थान के नकारात्मक पहलुओं से रूबरू होने का बहुत ही बढ़िया मौका दे देते हैं और प्रतिभावान कर्मचारियों को साथ जोड़ने की उनकी क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है।

हालांकि एक मुश्किल साक्षात्कार का विषाक्त होना जरूरी भी नहीं है। मसलन, एक महिला उम्मीदवार खुद को काफी असहज महसूस करने लगी जब साक्षात्कार पैनल में मौजूद एक शख्स बोरियत होने का आभास देने लगा और दो बार जम्हाई भी ली। लेकिन वह उम्मीदवार असल में 'तनावपूर्ण साक्षात्कार' के रूप में चर्चित विधा का अनुभव कर रही थी जिसका मकसद ही यह जानना होता है कि अमुक उम्मीदवार असहज एवं अनपेक्षित परिस्थितियों में किस तरह का बर्ताव करता है? उस समय सही या गलत जवाब का कोई मतलब नहीं होता है, साक्षात्कारकर्ता तो यह जानना चाहता है कि उस समय उम्मीदवार का बरताव कैसा है? इसके जरिये यह जांचने की कोशिश की जाती है कि तनावपूर्ण हालात में कोई उम्मीदवार किस कदर विश्वास एवं अनुकूलता का परिचय देता है।

तनावपूर्ण साक्षात्कार पेचीदे सवालों की शक्ल भी ले सकता है जिनमें से कुछ सवाल सुनने में भले ही आसान लगें लेकिन सारगर्भित जवाब देने के लिहाज से मुश्किल होते हैं। गूगल से ऐसे साक्षात्कार के कई वाकये सुनने को मिले हैं। करियर वेबसाइट ग्लासडोर ने गूगल में साक्षात्कार के दौरान पूछे गए कई पहेलीनुमा सवालों की एक झलक दी है। मसलन, अकाउंट स्ट्रेटजिस्ट पद के लिए साक्षात्कार देने आए एक उम्मीदवार से पूछा गया, 'आप अपने पालतू कुत्ते को ऑफिस लाना चाहते हैं लेकिन आपकी टीम के एक साथी को कुत्तों से एलर्जी है तो आप क्या करेंगे?' इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिस्ट पद के साक्षात्कार में पूछा गया, 'एक सिक्के को 1,000 बार उछाला गया और 560 बार हेड आया। क्या आपको यह सिक्का पूर्वग्रह से ग्रसित लगता है?' इसी तरह एक इंटर्न से एक विमान में समा सकने वाली टेनिस बॉल की संख्या के बारे में अंदाजा लगाने को कहा गया था।

ये सवाल तनावपूर्ण साक्षात्कार के क्लासिक उदाहरण हैं जिनके जरिये किसी उम्मीदवार की रचनात्मक सोच और समस्या का संभावित समाधान पेश करने की उसकी क्षमता के बारे में अंदाजा लगाया जाता है।

ऐसे ही एक साक्षात्कार में एक बेहद सफल पेशेवर से पूछे गए पहले सवाल ने ही उसे असहज कर दिया था। उससे 'अपने करियर की विफलताओं के बारे में बताने' को कहा गया था। वह अपने करियर की सफलताओं के बारे में बात करने की सोचकर आया था कि वह किस तरह करोड़ों रुपये का सौदा कराने में सफल रहा था? लेकिन उसका संभावित नियोक्ता तो उसकी नाकामियों के बारे में जानना चाह रहा है। उसने कुछ बातें बताई लेकिन अगले सवाल ने तो उसे और भी तनाव में ला दिया 'आपको बोरियत कब होती है?' इस सवाल का कोई रोचक जवाब दे पाने में उम्मीदवार को काफी परेशानी हुई लेकिन वह गलत राह पर जा रहा था। मानव संसाधन (एचआर) के प्रमुखों का मानना है कि ऐसी स्थितियों में स्मार्ट एवं ईमानदार जवाब आम तौर पर परिपक्व इंसान को आम लड़कों से अलग कर देते हैं।

अगर एक पेशेवर को यह लगता है कि उसे नौकरी नहीं देने या अपमानित करने के लिए ही जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे गए हैं तो वह गलत है। ऐसे सवाल इस बात की स्वीकारोक्ति हैं कि कॉर्पोरेट जीवन में परीलोक जैसा कुछ नहीं होता है और नाकामी अपरिहार्य है। इसके पीछे सोच यह जानने की होती है कि किसी पेशेवर ने अपनी नाकामियों से क्या सबक सीखे हैं? कभी-कभी साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति अनपेक्षित आचरण से उम्मीदवार का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मसलन, साक्षात्कारकर्ता एक ही तरह का तकनीकी सवाल कई बार पूछ सकता है ताकि यह संदेश दे सके कि उसे जवाब समझने में दिक्कत हो रही है। इस स्थिति में उम्मीदवार साक्षात्कारकर्ता की नासमझी को लेकर बेचैन हो सकता है।

हालांकि कुछ एचआर विशेषज्ञों का यह मानना है कि साक्षात्कार के दौरान तनाव का बखूबी सामना करने वाले पेशेवरों का काम के दौरान भी तनाव से बेहतर ढंग से निपट पाने का यह सिद्धांत गलत है। तनावपूर्ण साक्षात्कार की विवादप्रिय प्रकृति होने से लोग सावधान और रक्षात्मक रुख अख्तियार कर लेते हैं जिससे साक्षात्कारकर्ता उनके असली व्यक्तित्व एवं क्षमताओं के बारे में नहीं देख पाते हैं। भले ही इस बारे में ज्यूरी की राय आ चुकी है लेकिन बढ़िया ढंग से गुजर जाने वाले एक तनावपूर्ण साक्षात्कार का यह एक उदाहरण है। कुछ प्रतिकूल सवालों का संतुलित ढंग से जवाब दे चुकी एक उम्मीदवार से यह पूछा गया कि वह किसी मुश्किल शख्स के साथ काम करने से जुड़ा अनुभव बताए। उस महिला ने मुस्कराते हुए फौरन जवाब दिया, 'पहले मुझे यह बताने की इजाजत दीजिए कि मुझे कब मुश्किल साक्षात्कारकर्ताओं का सामना करना पड़ा है?' उस उम्मीदवार को नौकरी पर रख लिया गया।

कानाफूसी

रजनीकांत का चुनावी आगाज

यह सवाल कई लोगों के मन में है कि सुपरस्टार रजनीकांत आखिर कब चुनावी राजनीति में शामिल होंगे? अगर उनके खेमे से आ रहे संकेतों को समझा जाए तो ऐसा बहुत जल्दी हो सकता है। 68 वर्षीय रजनीकांत हाल के दिनों में अपनी विभिन्न योजनाओं को पूरा करने में अत्यधिक व्यस्त रहे हैं। रजनी मक्कल मंदरम नामक उनका संस्थान पिछले दो वर्ष से चल रहा है हालांकि उन्होंने बार-बार कहा है कि वह 2019 के आम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन तमिलनाडु में अगले विधानसभा चुनावों में वह शिरकत कर सकते हैं। कुछ दिन पहले त्रिची में उनके भाई सत्यनारायण राव गायकवाड़ ने कहा कि रजनीकांत 23 मई के बाद इस संबंध में घोषणा कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तथा सातवें चरण का मतदान 19 मई को होगा तथा मतगणना 23 मई को होगी।

राजनीतिक वापसी?

ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्होंने 2011 में ममता बनर्जी के हाथों वाम मोर्चे की पराजय के बाद सक्रिय राजनीति से कमोबेश संन्यास ले रखा है, वह दोबारा राजनीति में वापस आने का मन बना रहे हैं। माकपा के मुखपत्र गणशक्ति को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने राज्य के माकपा काडर को एक किस्म की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि तृणमूल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना वैसा ही है जैसे गर्म तवे से उछलकर सीधे आग में कूदा जाए। उन्होंने कहा कि तृणमूल और भाजपा की मिलीभगत है और इस किस्म की राजनीति को खत्म करना आवश्यक है।

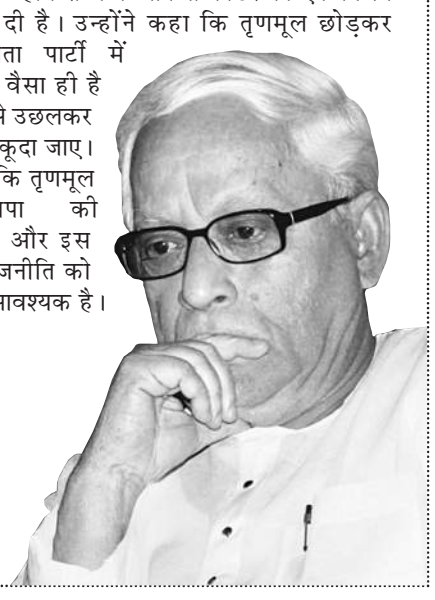

आपका पक्ष

डिजिटल गोल्ड संबंधी नियमों की जरूरत

देश में सोना एक अहम तथा कीमती लोकप्रिय धातु के रूप में माना जाता है। लेकिन डिजिटल युग ने इसका भी स्वरूप बदल दिया है। अब डिजिटल सोना भी बाजार में बिकने लगा है। कई बैंक डिजिटल सोना या गोल्ड बॉन्ड बेच रहे हैं। इसमें सोना भौतिक रूप से नहीं मिलता है बल्कि एक दस्तावेज के रूप में खरीदे गए सोने का वजन, कैरट तथा उस दिन का मूल्य लिखा जाता है। विश्व स्वर्ण परिषद ने डिजिटल गोल्ड के लिए नए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसमें निवेशकों के साथ डिजिटल गोल्ड खरीदने से संबंधित सेवाएं देने वाली इकाइयों के लिए नियम तय किए गए हैं। ऑनलाइन सोने की खरीद या डिजिटल सोने की खरीद में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नियम कानून जरूरी थे। कई ई-कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन सोना बेच रही हैं। इसके तय मानक क्या होने चाहिए इसका मापदंड भी होना चाहिए। वहीं ग्राहकों को ऑनलाइन कंपनियों द्वारा फर्जीवाड़े से बचाने के लिए भी नियम कानून होने चाहिए। अगर कोई 24 कैरट शुद्धता वाले सोने का 10 ग्राम का सिक्का ऑनलाइन कंपनी से खरीदता है तथा ग्राहक के पास नकली सोना पहुंचता है तो ऐसे में ग्राहक विशुद्ध रूप से ठग का शिकार हो जाता है। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो मामला साइबर क्राइम या फिर धोखाधड़ी का बनता है जिसके बाद पुलिस कार्रवाई होती है। डिजिटल फर्जीवाड़े में भी साइबर क्राइम का मामला बनता है। बहरहाल विश्व स्वर्ण परिषद के नए दिशानिर्देशों से ग्राहकों का काफी होगा। परिषद के अनुसार दुनिया में इस समय 200 से अधिक इकाइयां डिजिटल गोल्ड की पेशकश कर रही हैं। इनमें सबसे बड़ी इकाई के पास निवेशकों का अरबों डॉलर मूल्य का सोना है। ये इकाइयां यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक के बाजारों में हैं। भारत में पिछले दो वर्षों में तीन इकाइयां बाजार में उतर चुकी हैं। यहां करीब 8 करोड़ डिजिटल गोल्ड खाते खोले गए हैं। ऐसे में इसकी सुरक्षा संबंधी पहलू अहम हो जाते हैं। इसके लिए नए नियम कानून जरूरी हो जाते हैं। स्वर्ण परिषद की पहल सराहनीय है जिससे किसी फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिल सकती है।

विश्व स्वर्ण परिषद ने डिजिटल गोल्ड संबंधित नए दिशानिर्देश तय किए हैं

मोहित कुमार, नई दिल्ली

फ्लैट खरीदार को मिले राहत

रियल एस्टेट की नई परियोजनाएं रेरा द्वारा कवर की गई हैं। मंजूरी या वित्तीय मुद्दों के कारण जो परियोजनाएं चल रही हैं, पूरी हो गई हैं या अटकी हुई हैं, वे इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। इसलिए कई फ्लैट खरीदारों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। जिन बिल्डरों ने रेरा लागू होने से पहले परियोजनाएं शुरू की थीं, उन्होंने खुद ही मनमर्जी से परियोजना पूरा करने की तारीख बदल ली और रेरा में पंजीयन करा लिया। रेरा ने इसमें कोई आपत्ति नहीं दर्ज की और अब चूंकि बिल्डर ने पर्याप्त समय ले लिया है तो कोई भी उनसे सवाल नहीं पूछेगा। खरीद संबंधी मामले की सुनवाई में भी बहुत देरी होती है क्योंकि प्रतिदिन केवल 100 से 150 मामलों की ही सुनवाई होती है और अभी भी 5,000 आवेदन सुनवाई के लिए लंबित हैं।

कमलेश शर्मा, नोएडा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।